ties for their participation in Bharat Bandh programme on the 15th March 1988 and 30th August, 1989;

(b) whether Government are taking any steps to revoke the above penalties; if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS) (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The information is not readily available. The same is being collected from all the field units and will be laid on the Table of the House.

(b) As regards the Bandh on 15-3-88, the Government issued order on 30th August 1988 that in the case of those who had applied for leave for genuine reasons, and in the case of those who applied for leave stating that they had neither the intention nor did they intend to participate in the Bandh and that their absence was due to circumstances beyond their control e.g. on account of break-down of transportation services, picketing etc leave due and admissible might be sanctioned, provided leave is applied for within a week of receipt of the instructions and the leave sanctioning authority is satisfied of the genuineness of the reason.

Where absence on 30-8-89 was treated as dies-non, the same has been ordered to be treated as leave due and admissible on the request of the officials. The disabilities under FR-17-A imposed against officials found to have also indulged in other misconduct are to continue.

(c) Does not arise.

1384. [Transferred to 1st August, 1991]

साम्प्रदायिक दंगे

1385. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1990 से 30 जून, 1999 की अवधि के दौरान राज्यवार कितने साम्प्रदयिक दंगे हुए तथा वे किन-किन स्थानों पर कौन-कौन सी तारीखों को हुए तथा इन दंगों में कितने मारे गये और घायल हुए और प्रत्येक राज्य में कितने मूल्य की संपत्ति नष्ट हुई ।

(ख) उनके मुख्य कारण क्या-क्या थे ; और

(ग) सरकार भविष्य साम्प्रदायिक दंगों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है [देखिए परिशिष्ट 159 अनुपत्र संख्या 37]

(ग) लोक व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों को समस्याओं को हल करना होता है तथा उनके उपचारी उपाय करने होते हैं । जब कभी अनुरोध किया जाता है तो राज्य सरकारों को अतिरिक्त बल उपलब्ध करवा कर केन्द्र सरकार उनकी सहायता करती है, हमने भी राज्यों को इस प्रकार की बातों की रोकथाम करने के कुछ सुझाव दिए है । जिनसे देश में साम्प्रदायिक माहौल खराब होता हो । राष्ट्रीय एकता परिषद भी साम्प्रदायिकता की बुराईयों की रोकथाम करने के लिए रास्ते और उपाय तलाश करने की कोशिश कर रही है ।

Inclusion of Gorkhali in Eighth schedule of the Constitution

1386. SHRI RATNA BAHADUR RAI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation for the inclusion